

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

स्मार- 11

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
(भवन अंचल, गया जी/आरा/छपरा/मोतिहारी/ संरचना अंचल/
पटना भवन अंचल, पटना/विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार/
भवन निरूपण अंचल सं0-02 को छोड़कर)
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 18/6/26

विषय:- Material for preparation of Annual Report of the National Commission for SCs for the year 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में।
प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-8629 दिनांक-19.05.2026, विभागीय पत्रांक-10252(भ) अनु0, दिनांक-17.11.2025 एवं पत्रांक-333(भ) दिनांक-12.02.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रासंगिक पत्रांक-8629 दिनांक-15.05.2026 संलग्न करते हुए कहना है कि Material for preparation of Annual Report of the National Commission for SCs for the year 2024-25 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु वांछित सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जिससे संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि अपने अंचल एवं अधीनस्थ प्रमंडलों में उक्त से संबंधित वांछित सूचना विहित प्रपत्र में अविलंब B.C.D. S.E वाट्सऐप ग्रुप एवं विभागीय ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(Handwritten signature)

(अवधेश नंदन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।



पत्र संख्या-11/आ0 वि0-26/2025 सा0प्र0 8699

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

दिवाकर मणि,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव, / सभी विभागाध्यक्ष,
सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 15.5.26

विषय :- Material for preparation of Annual report of the National commission for SCs for the year of 2024-25 के संबंध में।

प्रसंग :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-17420 दिनांक-18.09.2025, पत्रांक-20159 दिनांक-29.10.2025, पत्रांक-845 दिनांक-13.01.2026 एवं पत्रांक-8453 दिनांक-09.04.2026.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा Material for preparation of Annual report of the National commission for SCs for the year of 2024-25 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने हेतु कतिपय कड़िकाओं के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि कतिपय विभाग द्वारा उक्त से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र के अनुसार उपलब्ध नहीं कराते हुए इससे इतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण डाटा संकलित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रकार के कार्यालयों से यथावांछित आंकड़े समेकित कर यथाशीघ्र विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 01 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय/संलग्न कार्यालयों आदि से प्रेषित आंकड़े सीधे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

अनु० यथोक्त।

श्रीमती सुकनी
20/5/26

विश्वासभाजन

(दिवाकर मणि)

सरकार के अवर सचिव।

4298
18.5.26

36

ई-मेल

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-5जी०/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग(खंड-1)-03/19 5245

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग/

योजना एवं विकास विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 2/9/25

विषय:-**Materials for Preparation of Annual report of the National Commission for SCs for the year 2024-25** के संबंध में।

महाशय,

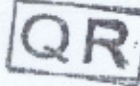
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने हेतु कतिपय कंडिकाओं के अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जिसमें से कुछ कंडिकाएँ आपके विभाग से संबंधित हैं।

अतः अनुरोध है कि संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव।

Email



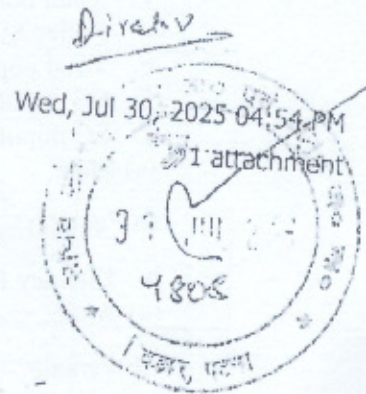
secy-welfare-bih

Materials for preparation of Annual Report of the National Commission for SCs for the year 2024-25 - regarding.

From : Arunabha Bhattacharyya <arunabh.b@nic.in>

Subject : Materials for preparation of Annual Report of the National Commission for SCs for the year 2024-25 - regarding.

To : secy-welfare-bih <secy-welfare-bih@nic.in>, DGP, Bihar <dgp-bih@nic.in>, secretary-welfarejharkhand@gov.in, dgp@jhpolic.gov.in
Cc : Director, National Commission for Scheduled Caste <dirncsc-bih@nic.in>



I am directed to enclose a format seeking materials for drafting Annual Report of the Commission for the year 2024-25. As you kindly aware that at the end of every financial year, the Commission prepares its Annual Report for submission before the Hon'ble President of India who in turn, forward the report to the MSJE for discussion in both houses of Parliament.

As preparation of report has significant importance, it is earnestly requested to forward the requisite material as per format with a week time for in corporation in draft AR for the year 2024-25.

This may kindly be treated as most urgent.

Yours faithfully,

A. Bhattacharyya
Asstt. Director
National Commission for SCs
Patna State/Regional Office
Mob. 9163668450

Data to seek from the State Govt. of Bihar Jharkhand.docx
22 KB

5366
07/08/25

21-10-2024
527/27
21
15-15-2025

15/11/25
20/9/25

34

34

Data to be furnished by the State Governments of Bihar & Jharkhand

1. State Profile

- a. Name of the State:
- b. Total number of districts:
- b. Blocks:
- c. Total number of villages:
- d. Police Stations:
- e. Total population:
- f. SC population:
- g. SC population (%):

(a) Male:

(b)Female:

h. Literacy Rate (%) SCs:

(a) Male:

(b)Female

2. Emerging trends in SC boycott:
3. Caste prejudice in mid-day-meal:
4. Honor killing Cases:
5. Deaths due to Manual cleaning of sewers:
6. Manual Scavengers Data and death due to manual cleaning of sewers etc.
7. Constitution of State/ District/ Sub-Division Monitoring Committees:
8. No. of State-Level Vigilance & Monitoring Committee (SLVMC) meetings held in States during 2024-25:
9. No. of District Level Vigilance & Monitoring Committee (DLVMC) meetings held in Districts during 2024-25 (Districtwise):
10. No. of Exclusive Special Courts at the end of March 2025:
11. No. of Districts with Designated Court:
12. No. of District with Exclusive Special Public Prosecutor/ Special Public Prosecutor:
13. Atrocity related:

Name of the State:

Annexure-A(a)

Statement showing cases registered with the police under different nature of atrocities on Scheduled Castes during the year 2022,2023, 2024 and 2025 (upto march 2025)

S. No	Nature of offenses against SCs	2022	2023	2024	2025 (upto March)	Remarks
1	Murder					
2	Grievous hurt					
3	Rape					
4	Arson					
5	Other offenses registered under: a.IPC and other Acts					

b. SCs STs (PoA) Act. 1989 and Amended Act, 2015					
c. PCR Act 1955 only					
d. Number of FIRs registered after the intervention of the Courts under section 156(3) of Cr. PCr					
Sub Total:					
Grand Total:					

14. State Employee position including SC employees in the State Govt. Services (as on 31.03.2025):

Level	Total number of Employees	SC	% of SC employees

15. Group wise man in position, vacancy position, percentage of man under PSUs (as on 31.03.2025):

Direct Recruitment:

S.No.	Name of Govt. undertakings	Name of Group	Sanctioned Strength as on 31.03.2025	Man in position against SC as on 31.03.2025	% in man in position against SC	Vacancy position against SC as on 31.03.2025	% on vacancy position against SC

Promotion:

S.No.	Name of Govt. undertakings	Name of Group	Sanctioned Strength as on 31.03.2025	Man in position against SC as on 31.03.2025	% in man in position against SC	Vacancy position against SC as on 31.03.2025	% on vacancy position against SC

32

16. Employee data in respect of percentage of SC employees Representation of SC Employees in State Government Service, PSUs (as on 31.03.2025):

Group of posts	Total no. of employees	No. of SC employees	% of SC employees	Shortfall
Group A				
Group B				
Group C				
Group D				
Sweepers				
Total				

17. Number of SC Officers in higher posts list Joint Secretary/ Secretary Level (as on 31.03.2025)

S.No	Name of Post	No. of SC Officers

18. Allocation and expenditure under SCSP for the years 2024-25: